SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

भारत–बांग्लादेश बनते बिगड़ते संबंध

गिरीश कांत पाण्डेय, Ph.D., **प्रवीण कड़वे,** Ph.D.,
गीतांजलि चन्द्राकर, Ph.D., रक्षा अध्ययन विभाग
शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
गिरीश कांत पाण्डेय, Ph.D.
प्रवीण कड़वे, Ph.D.
गीतांजलि चन्द्राकर, Ph.D.,

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 11/03/2024
Revised on : -----
Accepted on : 13/05/2024
Overall Similarity : 10% on 04/05/2024

शोध सार

भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों का प्रगाढ़ होना दक्षिण एशिया में राजनितिक अस्थिरता के बीच एक अच्छा संकेत है। बांग्लादेश की भूमि सीमा तीन ओर से भारत की सीमा से घिरी है और चौथी ओर बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत और बांग्लादेश 4096.7 किमी. सीमा रेखा साझा करते हैं जो भारत द्वारा किसी भी अन्य पड़ोसी देश के साथ साझा सीमा रेखा से लंबी है। भारत विश्व का पहला देश था, जिसने बांग्लादेश को एक पृथक एवं स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की थी और दिसंबर 1971 में इसकी स्वतंत्रता के तुरंत एक मित्र दक्षिण एशिया पड़ोसी के रूप में बांग्लादेश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये थे। भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति में बांग्लादेश एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। बांग्लादेश के साथ भारत के सभ्यतागत, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंध हैं। एक साझा इतिहास एवं विरासत, आशा एवं संस्कृति, संगीत, साहित्य और कला के लिये एक समान उत्साह आदि दोनों देशों को परस्पर संबद्ध करता है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के राष्ट्रगान के भी रचयिता रवींद्रनाथ टैगोर हैं। हालाँकि नदी जल विवाद (तीस्ता नदी के जल की साझेदारी), अवैध अप्रवासियों की सहायता और मादक द्रव्यों के व्यापार जैसे कई प्रमुख मुद्दे दोनों देशों के संबंध में अड़चन बने हुए हैं जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है।

मुख्य शब्द

आर्थिक सहयोग, व्यापक आर्थिक भागीदारी, समझौता (सीईपीए), भूमि सीमा, सीमा प्रबंधन.

विषय प्रवेश

भारत और बांग्लादेश के संबंध महत्वपूर्ण है और इनका मजबूत ऐतिहासिक आधार है। यदि इन संबंधों को

आपसी लाभ और आपसी सम्मान के साथ आगे बढ़ाया जाए तो इन संबंधों के मजबूत होने की संभावनाएं वास्तव में बहुत अधिक है। हमारी भौगोलिक निकटता, संस्कृतिक सामानता और साझा इतिहास हमारे संबंधों के मापदंड बनने चाहिए।

नीति निर्माता के साथ–साथ आम जनता के सामने जो चुनौतियां हैं वह अधिकतर ज्यादातर नकारात्मक विरासतों के कारण है जिनकी जड़े हमारे और औपनिवेशिक अतीत में हो सकती है जहां हमारे दोनों लोग उपनिवेशवादियों को फूट–डालो और राज करो की नीतियों के शिकार थे। इससे वह और विश्वास की भावना पैदा हुई है।

(Source: MyGov.in)

हमारे दोनों समाजों में ऐसी ताकते हैं जिन्होंने आपसे में झगड़े को कायम रखना और इस तरह हमें अलग रखने के लिए एक मनोविकृति पर खेल खेला है और खेलना जारी रखा है इसलिए यह जरूरी है कि हम एक नई नींव रखने के लिए मिलकर काम करें, जिस पर अतीत की सोच से मुक्त होकर मजबूत, व्यापक आधारित, टिकाऊ और सहकारी संबंध बनाया जा सके और हमारे लोगों के बीच अधिक विश्वास पैदा किया जा सके। संक्षेप में कहें तो समय की मांग है बदली हुई मानसिकता।

अभिसरण के क्षेत्र

व्यापार संबंध

- दोनों पक्षों ने अधिकारियों को व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते का (सी.ई.पी.ए.) पर बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया है जो लंबे समय से लंबित है। भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और एशिया में इसका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है।
- महामारी के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार लगभग 44 प्रतिशत की अभूतपूर्व दर से वर्ष 2020–21 में 10.78 अरब डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 18.13 अरब डॉलर हो गया है।
- बांग्लादेश की प्रमुख आयत वस्तुएं जैसे कपास, खनिज, ईंधन, मशीनरी, बिजली के उपकरण और अनाज भारत द्वारा दुनिया को निर्यात की जाने वाली शीर्ष वस्तुओं में से है।
- भारत तीन तरफ से बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है जिससे भारत बांग्लादेश का एक प्राकृतिक व्यापार भागीदार बन जाता है।

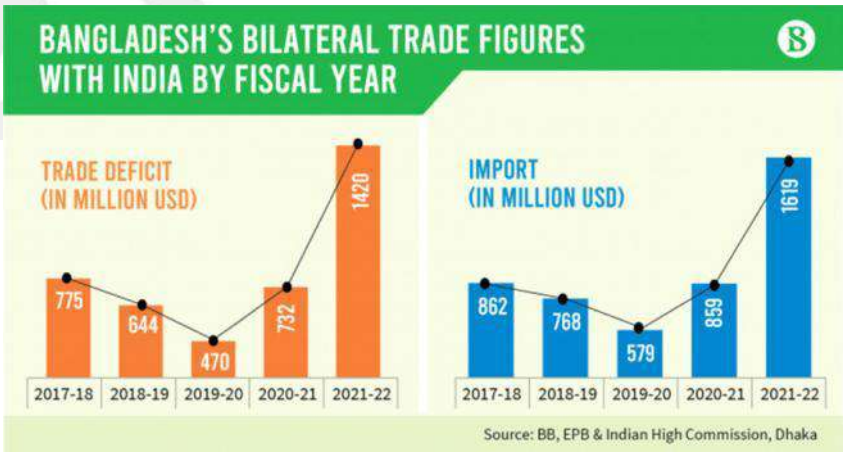

बांग्लादेश को भारतीय निर्यात	निर्यात का मूल्य डॉलर में
कपास	3.74 बिलियन
अनाज	2.32 बिलियन
खनिज ईंधन, तेल, आसवन उत्पाद	1.23 बिलियन
रेल्वे, ट्रामवे के अलावा अन्य वाहन	913.45 मिलियन
मशीनरी, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर	694.44 मिलियन

(Source: testbook.com)

सीमा प्रबंधन और नदी जल

- इन दो मुद्दों पर दिल्ली और ढाका के बीच ऐतिहासिक रूप से मतभेद रहे हैं, अब महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
- दोनों देश जीरो लाइन के 150 गज के भीतर सभी लंबित विकास कार्यों को पूरा करने के लिए काम में तेजी लाने के लिए सहमत हुए हैं, जिससे एक शांतिपूर्ण और अपराध मुक्त सीमा बनाए रखने के लिए त्रिपुरा सेक्टर से शुरू होने वाली बाड़ लगाना शामिल है का स्वागत किया।
- कुहसियारा नदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निश्चित सीमा बनाने का निर्णय।
- बांग्लादेश और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सभी बकाया बिंदुओं पर सीमा पर बाड़ लगाने की सुविधा के लिए समझौता।
- वैध दस्तावेजों के साथ यात्रा करने वाले बांग्लादेशियों ने भारत से भारतीय बंदरगाहों से प्रवेश और निकास पर सभी प्रतिबंधों को धीरे–धीरे हटाने के लिए कहा है।

रक्षा सहयोग

- बांग्लादेश अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है नए हथियारों को शामिल कर रहा है और अपने फोर्स गोल 2030 के अनुरूप बुनियादी ढांचे में सुधार कर रहा है।
- भारत के पास इन आवश्यकताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पूरा करने की क्षमता है जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।
- ढाका परंपरागत रूप से अपनी रक्षा जरूरत के लिए बीजिंग पर निर्भर रहा है, चुकि दिल्ली के साथ संबंधों में अधिक विश्वास है इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि सामरिक सहयोग आर्थिक संबंधों के साथ तालमेल बिठा सके।
- भारत और बांग्लादेश की एक साझा सीमा है जो 4096.7 किलोमीटर लंबी है, जो इसे एक पड़ोसी के साथ देश की सबसे लंबी भूमि सीमा बनाती है।
- जून 2015 में अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान–प्रदान के बाद भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता (एल बी ए) लागू हुआ।
- दोनों देशों के बीच विभिन्न संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं जिससे सेना के लिए अभ्यास संप्रति और नौसेना के लिए अभ्यास मिलन शामिल है।

बेहतर कनेक्टिविटी

- सीमा क्षेत्र में बेहतर संपर्क के लिए तटीय संपर्क सड़क, रेल और अंतर्देशीय जलमार्गों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं।
- भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मंगला बंदरगाहों के माध्यम से मल्टी मॉडल फेंट का ट्रायल रन सफल रहा है इसलिए दोनों देश इस मार्ग के शीघ्र पूरा होने और संचालन की तलाश कर रहे हैं।

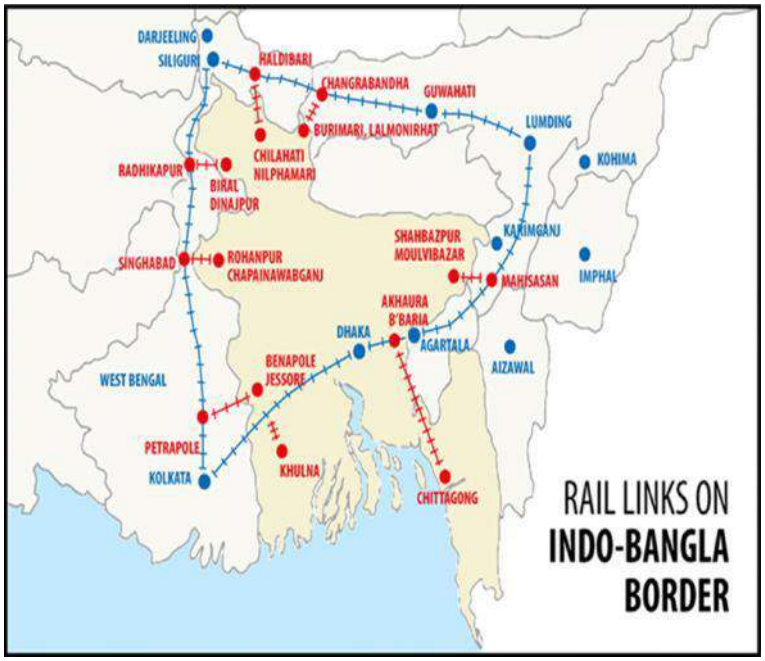

(Source: MyGov.in)

आर्थिक सहयोग

- दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बांग्लादेश है। भारत में 2018–19 वित्तीय वर्ष (अप्रैल–मार्च) में बांग्लादेश को 9.21 अरब डॉलर का निर्यात किया जबकि बांग्लादेश ने उसे दौरान भारत से 1.022 अरब डॉलर का आयात किया।
- वर्ष 2011 से दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) ने भारत को बांग्लादेशी निर्यात के लिए शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त पहुंच प्रदान की है।

पड़ोस की कूटनीति के लिए रोल मॉडल

- बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने विनम्रता पूर्वक भारत बांग्लादेश संबंधों को दुनिया भर में पड़ोस की कूटनीति के लिए एक आदर्श के रूप में वर्णित किया। लेकिन इस तरह के रिश्ते को मजबूत रहने और विकसित होने के लिए सावधानी से पोषित करने की जरूरत है।
- भारत बांग्लादेश संबंधों में बांग्लादेश भारत की विदेश नीति में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि अब भारत से निकटता और देश की ''पड़ोसी पहले नीति'' के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में है।
- भूमि सीमा समझौता वर्ष 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि के आदान–प्रदान के साथ संपन्न हुआ था जिसमें लोगों के लिए भारतीय बांग्लादेश नागरिकता चुनने का विकल्प था। यह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना थी जिससे दोनों देशों को लाभ हुआ।
- वर्ष 2017 में एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें भारत से रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट (एल. ओ. सी.) में 10 बिलियन डॉलर द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए बढ़ी हुई कनेक्टिविटी उच्च प्रभाव वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और तंत्र पर जोर दिया गया था।

ऊर्जा

- बांग्लादेश में ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण एनटीपीसी द्वारा संयुक्त उद्यम में रामपाल में 1,320 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र बनाया जा रहा है।

- अदानी समूह द्वारा निर्मित झारखंड के गोड्डा में एक 1600 मेगावाट बिजली संयंत्र अगले साल दिसंबर तक समर्पित ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करेगा।
- असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से मैत्री पाइपलाइन पूरा करने होने के करीब है और बांग्लादेश के पार्वतीपुर में पेट्रोलियम उत्पादों की डिलीवरी करेगी।
- भारत बांग्लादेश संबंधों में रूपपुर परमाणु ऊर्जा सुविधा के निर्माण की शुरुआत के साथ भारत ने भी अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में बांग्लादेश के साथ मिलकर काम किया है।
- भारत ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए बांग्लादेश को 1100 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए तैयार है।
- भारतीय कंपनियां 3600 मेगावाट से अधिक की संयुक्त क्षमता वाली बिजली परियोजनाओं पर काम कर रही है।

आतंकवाद

- सीमाएं आतंकवादी घुसपैठ के लिए अति संवेदनशील है। बांग्लादेश में आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए समूह बन गए।
- दोनों देश आतंकवाद और उग्रवाद के सभी खतरों को दूर करने के लिए द्विपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहें है।
- नकली भारतीय मुद्रा नोटों, ड्रग्स और हथियारों और गोला बारूद की तस्करी, महिलाओं और बच्चों की तस्करी के खतरे से लेकर मानव तस्करी में शामिल व्यक्तियॉ, दलालों, एजेटों के खिलाफ सम्मिलित कार्यवाही करने पर जोर दे रहें है।
- बांग्लादेश ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने में कुछ हद तक जरूर सफलता अर्जित की है लेकिन उग्रवादी समूह देश में अब भी सक्रिय बने हुए है। नए उग्रवादियों की भर्ती सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि अब उन्हें टेक्नोलाजी के अधिक जानकार आतंकियों से निपटना पड़ता है। नए युग के आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को निश्चित रूप से अधिक सुदृढ़ होना होगा।

चिंता के क्षेत्र

नागरिकता संशोधन अधिनियम

- भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर बांग्लादेश में चिंता है।
- यह अटूट संबंधों का एक प्रमाण है कि ऐसी राजनीति में ढाका के साथ संबंधों को खराब नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत को चीजों को हल्के में लेना चाहिए।

रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या

बांग्लादेश लगभग 11 मिलियन रोहिंग्या मुसलमानों का घर है। म्यांमार सेना ने उनके प्रस्थान को प्रेरित किया है। भारत के म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और वह ऐसे संबंधों को खतरे में नहीं डालना चाहता। मानवीय सहायता अभियान ''मिशन इंसानियत'' को चलाने के अलावा, भारत की संघर्ष को सुलझाने में कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है। परिणामस्वरूप, बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण विचलन आया है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने हाल ही में बांग्लादेश के तस्करों और अवैध प्रवासियों को निशाना बनाकर मार गिराया है। बांग्लादेश में, इससे सार्वजनिक आक्रोश फैल गया और बांग्लादेश राइफल्स ने बिना उकसावे के बीएसएफ से जुड़े भारतीय सेवा सदस्यों को गोली मार दी। कई टिप्पणीकारों ने इस वर्तमान धार्मिक सिद्धांत को बांग्लादेशी सेना पर कुख्यात आईएसआई के प्रभाव से जोड़ा है।

तीस्ता नदी जल विवाद

- हिमालय से उत्पन्न होने वाली और सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से होकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी (बांग्लादेश में जमुना नदी) में विलय होने वाली तीस्ता नदी के जल बटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच संभवतः सबसे बड़ा विवाद है।
- तीस्ता नदी सिक्किम के लगभग पूरे इलाकों को पार करने के साथ–साथ बांग्लादेश के बड़े क्षेत्र को भी पार करती है जिसके कारण यह इन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों की जल संबंधी आवश्यकताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

तीस्ता नदी – यह जिन राज्यों से होकर गुजरती हैं

(Source: MyGov.in)

- वहीं पश्चिम बंगाल के लिए भी तीस्ता नदी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सिक्किम और बांग्लादेश के लिए। इसे उत्तर बंगाल में आधा दर्जन जिलों की जीवन रेखा माना जाता है।
- गौरतलब है कि दोनों देश सितंबर 2011 में जल साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की अंतिम प्रक्रिया में थे, किंतु पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस पर आपत्ति जताई और इस समझौते को रद्द कर दिया गया।
- तीस्ता जल बंटवारे का लंबे समय से लंबित मुद्दा ढाका के लिए एक प्रमुख चिंता आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल सरकार के कारण अनसुलझा है।
- दोनों देशों के बीच तीस्ता जल बटवारा विवाद को सुलझाने के लिए अभी तक किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।
- हालांकि कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ लेकिन विवाद को सुलझाने के लिए नए पहल किये जा रहे हैं।

क्षेत्रीय भू राजनीति

- पड़ोस में चीनी घुसपैठ भारत के लिए चिंता का विषय रहा है चीन सक्रिय रूप से बांग्लादेश के साथ विपक्षी संबंधों को आगे बढ़ा रहा है।
- बांग्लादेश में तीस्ता नदी के जल प्रवाह को बढ़ाने के लिए एक बड़ी परियोजना के लिए चीन से सफलतापूर्वक संपर्क किया है
- पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश चीन के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियार बाजार है।
- वर्तमान में बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) में एक सक्रिय भागीदार है।

चीन का बांग्लादेश में दखल

- बांग्लादेश के दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र और बंगबंधु संचार उपग्रह सहित 25 से अधिक ऊर्जा परियोजनाओं को चीन द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। कई बंदरगाह विकास परियोजनाएं चल रही हैं। चीन की वन बेल्ट वन रोड पहल ने बांग्लादेश को भी फँसा दिया है, और चीन की भारत से निकटता सुरक्षा चिंताओं का कारण बनती है।
- बांग्लादेश में चीन का निवेश स्टॉक बढ़कर लगभग 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। बांग्लादेश में लगभग सात सौ चीनी कंपनियाँ काम कर रही हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए 5.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। तथ्य यह सच बताते हैं कि, बांग्लादेश के आधुनिकीकरण की यात्रा में, बीआरआई विजन 2041 और स्मार्ट बांग्लादेश के साथ सबसे उपयुक्त विकास सहयोग पहल है।

- भविष्य को देखते हुए, चीन ऐतिहासिक विकास के अवसरों को मजबूती से पकड़ने, हमारी आर्थिक पूरकता को पूरी तरह से संयुक्त प्रतिस्पर्धात्मकता में बदलने और उच्च के बैनर तले रणनीतिक एकीकरण को सक्रिय रूप से गहरा करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से नई सरकार के बांग्लादेशी दोस्तों के साथ काम करने के लिए तैयार है।

बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति

- मालदीव की तरह बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन, विपक्षी दलों की भारतीय उत्पादों के बायकॉट की अपील, बड़ा खतरा India Out Movement in Bangladesh अभियान के समर्थन में आए लोग कह रहे हैं कि भारत हमारे देश को खोखला कर रहा है। ऐसे में भारतीय उत्पादों का बहिष्कार किया जाना चाहिए और देश से भारत की दखल को कम करना चाहिए। वर्तमान प्रधानमंत्री को भारत से अच्छे संबंधों के लिए निशाने पर लिया जा रहा है।
- बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था। कई सर्वेक्षणों से भी ये पता चलता है कि बांग्लादेश के लोगों को विश्वास नहीं है कि जनवरी का चुनाव निष्पक्ष रूप से आयोजित किया गया था और ज्यादातर विपक्षी दलों ने जनवरी में हुए चुनावों का बहिष्कार किया था। कई देशों ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति के बारे में चिंता जताई थी लेकिन भारत ने इस पर कोई बयान नहीं दिया था। इसकी एक बड़ी वजह शेख हसीना का रुख भारत के लिए नरम होना भी माना गया।

भारत से क्यों खफा विपक्षी दल?

- भारत सरकार ने शेख हसीना के साथ मिलकर बीते सालों में कई अहम काम किए हैं। वहीं चीन भी बांग्लादेश से नजदीकी बढ़ाना चाहता है। लोकतंत्र और मानवाधिकार के मुद्दों पर हसीना सरकार की आलोचना से बांग्लादेश के चीन के करीब जाने का डर था इसलिए भारत ने बांग्लादेश चुनाव पर चुप्पी साधे रखी। एक ओर जहां शेख हसीना भारत को दोस्त कहती हैं तो बांग्लादेश नेश्नलिस्ट पार्टी जैसे विपक्षी दल आमतौर पर भारत को संदेह की दृष्टि से देखते रहे हैं। ऐसे में शेख हसीना का सत्ता में लौटना भारत के नजरिए से अच्छा था।
- बीएनपी समेत बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां ''इंडिया आउट'' अभियान को समर्थन दे रही हैं। ये दल भारत पर बांग्लादेश के चुनावों को प्रभावित करने और हसीना को समर्थन की बात कह रहे हैं। बड़ी संख्या में बनाए गए सोशल मीडिया अकाउंट से बांग्लादेश में बेचे जाने वाले भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का भी आह्वान कर रहा है। इसका कुछ असर भी दिखा है और बांग्लादेश के बाजार में भारतीय उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री में गिरावट का भी दावा किया गया है। हालांकि सरकार में शेख हसीना के होने की वजह से इस कैंपेन का असर बहुत ज्यादा ना होने की बात कही जा रही है लेकिन यह भारत की पड़ोस नीति के बारे में जरूर चिंता पैदा करता है।

पश्चिमी देशों का बांग्लादेश पर दबाव

- बांग्लादेश चुनाव में अमेरिका का अत्यधिक हस्तक्षेप से इस्लामपंथियों को बढ़ावा मिलेगा और देश का झुकाव चीन की ओर बढ़ेगा।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने बांग्लादेशी राजनेताओं, अधिकारियों और उसके सुरक्षा बलों के सदस्यों के खिलाफ वीजा प्रतिबंधों की धमकी दी थी, जो उसे लगता है कि चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने और विपक्षी दलों को नुकसान में डालने के दोषी हैं।
- अन्य पश्चिमी देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए समान प्रतिबंधों सहित कार्रवाई की धमकी दी है।

- भारत ने अमेरिका को आगाह किया गया है कि बांग्लादेश पर ज्यादा दबाव डालने से वह चीन की गोद में चला जाएगा। और बीएनपी और उसके इस्लामी सहयोगियों का एक एजेंडा है जो संभावित रूप से क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
- वास्तव में, चीन पहले ही बांग्लादेश को आश्वासन दे चुका है कि वह ''बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करने'' में समर्थन करता है और उसने इस तरह के हस्तक्षेप का विरोध करने में मदद करने का वादा किया है।
- यह अपरिहार्य है कि अत्यधिक हस्तक्षेप और बहुत अधिक दबाव का सामना करते हुए, बांग्लादेश चीन की ओर रुख करेगा और चीन अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ पक्ष लेने के लिए बहुत इच्छुक है।

निष्कर्ष

वैश्विक परिदृश्य में बदलते भू–अर्थशास्त्र की स्थिति में बांग्लादेश के साथ संबंधों को गहरा करना एक आवश्यकता बन गया है जो वैश्वीकरण और संरक्षणवाद को केंद्र में ले जाने की चाल को चुनौती दे रहा है। इसके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए इस क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी विकसित करना महत्वपूर्ण होगा। बांग्लादेश अपनी बढ़ती आर्थिक सफलता के साथ इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदारी प्रदान करता है और इसकी 8 प्रतिशत के साथ विकास दर को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में जाना जाता है। तेजी से विकसित हो रही भू राजनीति और बांग्लादेश में पूर्वी एशिया अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती उपस्थिति में निकटवर्ती पड़ोसी देशों में स्थाई पारस्परिक सहयोग पर आधारित रणनीति के साझेदारी भारत की पहले विदेश नीति में एक मूल्यवान स्तंभ होता है।

संदर्भ सूची

1. बिस्वास, एस., और साहा, एस.,(2018) सीमा प्रबंधन और भारत –पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, बांग्लादेश संबंधः चुनौतियॉ और संभावनाएँ, *इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन,* 83–97।
2. चौधरी, ए.आर. (2019) भारत–बांग्लादेश संबंधः क्षेत्रीय स्थिरता के लिए निहितार्थ, दक्षिण एशियाई सर्वेक्षण, 95–110।
3. दत्ता, एस. (2017) भारत–बांग्लादेश संबंधः अतीत, वर्तमान और भविष्य, *भारत त्रैमासिक,* 159–175।
4. www.bbc.com Access On -12 Feb. 2024
5. www.business-standard.com Access On -12 Feb. 2024
6. www.icwa.in Access On -20 Feb. 2024
7. www.mea.gov.in Access On - 22 Feb 2024
8. www.mod.gov.in Access On - 22 Feb 2024
9. www.nextias.com/ca/editorial-analysis Access On -25 Feb. 2024
10. www.orfonline.org Access On -22 Feb 2024
11. www.southasianvoices.org Access On -25 Feb. 2024
12. www.unacademy.com Access On -25 Feb, 2024
13. www.testbook.com Access On – 25 Feb. 2024
14. www.vajiramandravi.com Access On -22 Feb 2024

****